mal-nutrition and re-occurrence of the disease.

(iii) Need to withdraw the proposed like in Service charges levied by Mormugao Port Trust, Goa

*SHRI J S. PATIL (Thane) : Goa's iron ore export industry is facing a severe crisis due to the world-wide demand-recession. In addition to this, the proposed measure of Mormugao Port Trust to increase its service charges by 61 per cent has hit hard the ore export units of Goa. Two mine-owner exporters have already stopped functioning. A couple of more exporters are likely to close down their units due to steep service levy hike by Mormugao Port Trust. The ore industry which earns Rs. 140/- crores every year in foreign exchange will become irretrievably sick in near future rendering many workers jobless.

Mormugao Port Trust has raised service charges to make its mechanical ore handling plant self-sufficient. The operation of the plant is showing losses for the past two years. Iron ore exporters feel that losses can be wiped out by instilling more efficiently in the port's working and maintaining proper coordination in its activities. Mormugao Port Trust is making good its losses by increasing the service charges.

All the exporters associations in Goa have opposed the move of Mormugao Port Trust to increase its service charges and appealed to withdraw its hike. But their appeals have fallen on deaf ears. I, therefore, request the Government to take appropriate steps to withdraw the proposed hike in service charges and save the iron ore export industry of Goa from becoming extinct.

(iv) Need for financial help from central government to Uttar Pradesh for completing the ongoing irrigation projects

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य आधार है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अनेक सिंचाई योजनायें वर्षों से प्रारम्भ की गई हैं किंतु वित्तीय कठिनाइयों के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं। योजना की लागत क्रमशः बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं और वहां बंधे बंधियां एवं नलकूप बनाना आवश्यक है, उन क्षेत्रों में भी सिंचाई के नये कार्यक्रम नहीं चल पा रहे हैं। उक्त बड़ी सिंचाई योजनाओं का उनके क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। उदाहरण के लिए ज्ञानपुर पम्प नहर, सोन पंप नहर, देवकली पम्प नहर, कनहर बन्धा तथा अन्य मझोली एवं छोटी बंधियां तथा नलकूप इत्यादी मिर्जापुर, बनारस इत्यादि पूर्वी उत्तर के असिंचित क्षेत्रों के लिये अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग धन की कमी के कारण ऊक्त योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। साथ ही नयी योजनाएं भी नहीं चल पा रही हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए उक्त योजनाओं के लिए धन की सहायता प्रदान की जाये।

(v) *Re.* need for payment of funds by Central governments for modernisation of Bijnore Sugar Mills

श्री बंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, बिजनौर चीनी मिल की स्थापना 1983 में हुई थी और 1946 से लगातार यह मिल लीज पर चलाई जाती

*The Original speech was delivered in Marathi.

[श्री मंगल राम प्रेमी]

रही है, जिसका उद्देश्य मात्र लाभ कमाना था। परिणामस्वरूप मिल की मशीनरी अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हो गई है और यह मिल बीमार मिलो की सूची में आ गई। चीनी मिल के मजदूरों एवं स्थानीय काश्तकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1971 में राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया परन्तु अनेक कानूनी अड़चनों के कारण इस मिल का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका और लगातार यह घाटे में चलती रही। निरंतर पेराई क्षमता में गिरावट आती गई। इस समय इसकी पेराई क्षमता प्रदेश की अन्य मिलों की अपेक्षा सब से कम 1100 क्विंटल प्रतिदिन रह गई है, जबकि अन्य मिलों की क्षमता 2500 क्विंटल प्रतिदिन से अधिक है।

बिजनौर क्षेत्र ईख की खेती के लिए लगभग समस्त उत्तर प्रदेश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार द्वारा एक चीनी मिल लगाने के लिए 12.3.82 को एक लाइसेंस निर्गत किया गया। आस्ट्रेलियन तकनीक के आधार पर इसे आधुनिकीकरण हेतु परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई, ताकि कालांतर में इसकी पेराई क्षमता बढ़ा कर 4500 क्विंटल प्रतिदिन तक की जा सके। इस योजनान्तर्गत कुल व्यय 11 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4.80 करोड़ रु० प्रदेश सरकार एवं शेष धनराशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिया जाना है। परियोजना की सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं।

अतः कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में कारगर कदम तुरन्त उठाकर उक्त परियोजना को क्रियान्वित किया जाय और केन्द्र सरकार द्वारा देय राशि अविलम्ब भुगतान कराया जाये, ताकि बिजनौर चीनी मिल का आधुनिकीकरण हो सके और गन्ना किसानों एवं मजदूरों को समुचित लाभ पहुंच सके।

धन्यवाद

(vi) Demands of workers of Bijli Cotton Mills, Hathras (U.P.)

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हाथरस (उत्तर प्रदेश) के बिजली काटन मिल्स में हो रही अनियमितताओं, हेरा-फेरी तथा मजदूर विरोधी कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मिल नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की एक इकाई है। इसके प्रबंधकों ने ऐसी नीति अपना रखी है, जिससे मजदूरों में घोर असंतोष और रोष व्याप्त है। यदि उनकी समस्याओं का तुरन्त निराकरण नहीं किया गया, तो किसी भी वक्त स्थिति विस्फोटक बन सकती है।

मेरी मांग है कि मजदूर की यथोचित मांगे जैसे कि छुट्टियों का वेतन जो कि छुट्टियों औद्योगिक न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा मजदूरों को एवार्ड के तहत दी गई हैं, त्यौहारों की छुट्टियों का पूरा वेतन और वेतन वृद्धि, श्रमिकों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध, ग्रेचुयेटी की बकाया का भुगतान, श्रमिकों की तरक्की की नीति का पालन, श्रमिकों के लिये केन्टीन, रेस्टरूम आदि की व्यवस्था, शीघ्र पूरी की जानी चाहिए।